		2	3	4	5
20.	Rajasthan	107400	116567	4430.00	4213.30
21.	Sikkim	1352	1218	56.00	40.96
22.	Tamilnadu	184436	214888	7608.00	7269.39
23.	Tripura	15000	16297	618.00	540.29
24.	Uttar Pradesh	4163.54	445403	20508.00	20197.02
25.	West Bengal	182836	73818	7542.00	2959.40
26.	Andaman and Nicobar Islands	1726	1171	71.00	38.10
27.	Chandigarh	—	—	—	—
28.	Dadra and Nagar Haveli	372	372	15.00	14.89
29.	Delhi	—	—	—	—
30.	Daman and Diu	690	507	28.00	18.74
31.	Lakshadweep	159	81	7.00	6.59
32.	Pondicherry	1407	1407	58.00	36.2V
	ALI. INDIA TOTAL:	2569942	2539441	109843.00	95664.95

ग्रामीण विकास में शामिल स्वयंसेवी संगठन

2817. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दातव्य और स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता से कार्यान्वित ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए किए गए वर्षवार बजट प्रावधानों तथा इन पर वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं की निगरानी तथा इनके समुचित कार्यान्वयन हेतु अपनाई गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तम भाई पटेल): स्वयं-सेवी संगठन, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् की मार्फत ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाएं हैं जो जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास, जन-सहयोग, लाभार्थियों का संगठन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल-आपूर्ति कार्यक्रम के क्षेत्रों को कवर करती है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कापार्ट को रिलीज की गई निधियों तथा 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 (28.2.95 तक) कापार्ट द्वारा स्वयं-सेवी संगठनों को रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण (नीचे देखिए) संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए कापार्ट की अपनी प्रणाली है। इसने कई अनुभवी व्यक्तियों को मानीटरों के रूप में सूचीबद्ध किया है। परियोजनाओं की संस्वीकृति के पश्चात् निधियां उचित किस्तों में रिलीज की जाती हैं। प्रथम किस्त की रिलीज के पश्चात् स्वयं-सेवी संगठन को उचित अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। सामान्यतया इस स्तर पर सभी परियोजनाओं की निगरानी की जानी होती है। मानीटर की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां पाए जाने की स्थिति में स्वयं-सेवी संगठनों को उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक सलाह दी जाती है। परियोजनाओं के पूरा होने पर संगठन अंतिम प्रगति रिपोर्ट, लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है।

विवरण

1992-93, 1993-94 और 1994-95 (28.2.95 तक) के दौरान सरकार द्वारा कापार्ट को दी गई धनराशि तथा कापार्ट द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों को दी गई राशि

(रुपये करोड़ में)

योजना	1992-93		1993-94		1994-95 (28.2.95 तक)	
	मंत्रालय द्वारा कापार्ट को रिलीज की गई राशि	कापार्ट द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों को रिलीज की गई राशि	मंत्रालय द्वारा कापार्ट को रिलीज की गई राशि	कापार्ट द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों को रिलीज की गई राशि	मंत्रालय द्वारा कापार्ट को रिलीज की गई राशि	कापार्ट द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों को रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	7.50	9.72	16.99	12.58	15.00	13.06
जवाहर रोजगार योजना	12.00	8.30	10.00	10.76	6.00	6.96
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	6.00	4.52	8.59	9.54	9.00	5.94
गरीबी निवारण कार्यक्रम के लाभार्थियों का संगठन	1.40	1.77	2.50	2.44	2.50	1.66
ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों का संवर्धन	6.50	5.94	9.50	11.32	9.50	7.04
ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा)	2.80	2.24	4.50	4.32	3.00	2.11
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1.20	0.76	1.43	1.22	1.50	1.54
ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना	5.00	2.79	8.50	10.36	12.00	7.61
कुल:	42.40	36.04	62.01	62.54	58.50	49.92*

* इसके अलावा, कापार्ट की क्षेत्रीय समितियों को 3 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

भूमिहीन किसान

2818. **श्री अजीत जोगी:**
श्री सुशील बरोंगथा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1994 तक की स्थिति के अनुसार देश में भूमिहीन किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन किसानों को भूमि प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल: (क) जनगणना के समय भूमिहीन किसानों के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जाती है। तथापि 1991 की जनगणना के समय कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में ब्यौरे एकत्र किए गए थे। देश में (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) कृषि मजदूरों की संख्या 74,597,744 थी। कृषि मजदूरों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किसी नई योजना पर विचार नहीं किया